

प्रधानमंत्री द्वारा मलेशिया दौरे की समाप्ति पर मीडिया के समक्ष दिया गया वक्तव्य

दिनांक 14 दिसंबर, 2005

एयर इंडिया-1 विमान में

कुआलालम्पुर में हुई मेरी कई बैठकों के बारे में आपको नियमित रूप से बताया जाता रहा है। कुआलालम्पुर के मेरे दौरे की समाप्ति पर मैं समझता हूँ कि यह कहना ठीक होगा कि इस दौरे से मुझे *आसियान* के नेताओं से निरंतर घनिष्ठ हो रहे हमारे सहयोग और भागीदारी की दिशा में उनसे बातचीत करने का बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर मिला और साथ ही अधिकांश नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता करने का मौका भी मिला।

हमारे विचार से भारत-*आसियान* के सहयोग का वर्तमान स्तर हमारे द्वारा चयन की गई उस नीति का कार्यान्वयन है जो हमने लगभग डेढ़ दशक पहले अपनाई थी, जब हमने अपनी पूर्वोन्मुख नीति शुरू की थी। उस समय हमारा यह मानना था कि परस्पर लाभदायक बातचीत के लिए जो क्षमताएं मौजूद हैं उन्हें उपयोग में लाना तो दूर, पहचाना तक नहीं गया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब स्थिति बिल्कुल उलट है; दोनों पक्ष इस क्षमता के प्रति पूरी तरह सचेत हैं और हम जिस गति से इस क्षमता का उपयोग करने में समर्थ हैं, उस गति को लेकर हम लोगों में एक स्पष्ट अधीरता सी है। सच यह है कि *आसियान* की ओर से कम ही अधीरता दिखाई जा रही है। अन्य देशों के मेरे सहयोगियों ने ये विचार व्यक्त किए कि यदि हम तेजी से आगे बढ़ सकें तो बेहतर होगा। मैंने इसके बदले में इस अवसर पर उन्हें भारत-*आसियान* शिखर सम्मेलन और कई द्विपक्षीय बैठकों में पुनः यह आश्वस्त किया कि ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमारी आगे बढ़ने की दिशा सही है और हमारे पास घनिष्ठ आर्थिक सहयोग की ओर बढ़ने का इरादा भी मौजूद है। जिस गति से हम आगे बढ़ेंगे, उसमें हमें अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और भिन्न-भिन्न व्यापक विचारों, जिनको हमें अपने आर्थिक नीति-निर्धारण में व्यक्त करना है, को भी ध्यान में रखना होगा। मुझे विश्वास है कि *आसियान* के नेतागण इस सच्चाई को समझते हैं और वे अनेक क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए आतुर हैं।

भारत-*आसियान* सम्मेलन में मैंने अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किए जो सैटेलाइट संपर्क (कनेक्टिविटी) और अंग्रेजी भाषा के शिक्षण जैसे क्षेत्रों में भारत की क्षमताओं का उपयोग करने पर आधारित हैं और इस पर हमें काफी अच्छा प्रत्युत्तर मिला है। वास्तव में, *आसियान* के हमारे सहयोगियों ने मुझे सुझाव दिया कि ऐसा परियोजना-आधारित सहयोग जैव-प्रौद्योगिकी जैसे संबंधित क्षेत्रों में बढ़ाया जाए जिसकी शुरुआत करने पर हम सहमत हो गए हैं। मुझे एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया जो क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर बातचीत को आगे बढ़ाने से सम्बंधित था। आतंकवाद का मुकाबला करने और समुद्री सुरक्षा बढ़ाने हेतु और अधिक सहयोग करने का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। ये दोनों ही सुझाव हमारे लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। हम इन मुद्दों पर द्विपक्षीय आधार पर कुछ *आसियान* देशों के साथ पहले से ही सहयोग कर रहे हैं। इन मुद्दों पर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

जैसा कि आप लोगों को मालूम है, भारत-*आसियान* मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए), जिस पर बातचीत चल रही है, पर व्यापक टिप्पणियाँ की गईं। *आसियान* के सदस्यों ने भारत द्वारा प्रस्तावित नकारात्मक बातों की सूची पर चिंता जताई है। मैंने उनकी चिंता को नोट कर लिया है और उन्हें बताया है कि इस मुद्दे को परस्पर संतोषप्रद ढंग से सुलझा लिया जाएगा। हम मुक्त व्यापार समझौते को हर हालत में 1 जनवरी, 2007 से लागू करने की समय-सीमा बनाए रखेंगे। *आसियान* के मेरे सहयोगियों ने भी *आसियान-इंडिया ओपन स्काइज अरेंजमेंट* में अपनी

रुचि व्यक्त की है। हम इस बात की जांच करेंगे कि इसे कैसे लागू किया जाए। मैंने इन सब पहलुओं का उल्लेख किया है ताकि *आसियान* के साथ हमारे उत्तरोत्तर बढ़ते सम्बंधों की व्याख्या की जा सके।

आज इससे पहले हम प्रथम पूर्वी-एशिया सम्मेलन में मिले। इस बैठक का महत्व और प्रभाव लगभग प्रत्यक्ष है। इसकी संरचना, इसके लिए तैयार किया जा रहा एजेंडा और इसकी रूपरेखा इसे मजबूती प्रदान करेगी जिससे यह वैश्विक मामलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। इस समूह में शुरू से ही भारत की उपस्थिति एक ऐसा अवसर है जिसे हम काफी महत्व देते हैं। निश्चित ही यह एक अच्छा कार्य है, जो प्रगति पर है। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि यह समूह कार्य करने की इच्छा रखता है न कि काम करने से रोकने की। मैं उनकी इस भावना को देखकर प्रसन्न हूँ। एक बनते हुए वैश्विक संतुलन में पूर्वी-एशिया का हमेशा महत्व रहेगा। भारत की भागीदारी इसके महत्व को और बढ़ायेगी।

कुआलालम्पुर में मैंने अनेक द्विपक्षीय बैठकों में भी भाग लिया। मेरी पहली मुलाकात प्रधानमंत्री श्री बदामी से हुई जिसमें हम दोनों ने द्विपक्षीय समझौतों और *आसियान* तथा पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलनों से की गई अपनी आशाओं की समीक्षा की। मैंने वियतनाम के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की और हमने हाइड्रोकार्बन और रक्षा जैसे क्षेत्रों में अपने सहयोग को आगे बढ़ाने की क्षमता की समीक्षा की। हम जैव-प्रौद्योगिकी जैसे उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में वियतनाम की रुचि पर विचार करने की भी कोशिश करेंगे। मैंने प्रधानमंत्री श्री कोइजुमी के साथ हुई अपनी बैठक में जापान के साथ हमारे सहयोग की भी व्यापक समीक्षा की। हमने संख्यात्मक और गुणणात्मक दोनों ही दृष्टि से अपने संबंधों को आगे बढ़ाने हेतु कार्य करने का निर्णय किया। जापान के प्रधानमंत्री ने मौजूदा और उभरते हुए मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर सहयोग करने के महत्व पर जोर दिया। इन मुद्दों में आधारभूत ढांचे की संभावनाएं, आपदा प्रबंधन में सहयोग और जी-4 समूह में चल रही हमारी भागीदारी शामिल हैं। मैंने आईटीईआर में भारत के प्रवेश पर जापान के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री श्री कोइजुमी को धन्यवाद दिया और उन्हें विश्वास दिलाया कि भारत की पूर्वोन्मुख नीति में जापान का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मैंने आईटीईआर में भारत के प्रवेश का समर्थन करने के लिए कोरिया के राष्ट्रपति को भी धन्यवाद दिया और भारत को प्रभावित करने वाले एन.एस.जी. प्रतिबंधों को हटाने में कोरिया के समर्थन के महत्व की ओर भी उनका ध्यान आकर्षित किया। म्यांमार के प्रधानमंत्री के साथ हुई अपनी बैठक में हमने एक-दूसरे के देश की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग करने की हमारी रुचि को भी दोहराया गया। लौटने से ठीक पहले मैं चीन के प्रधानमंत्री श्री वेन-जियाबाओ से भी मिला। हमने प्रधानमंत्री श्री वेन की अप्रैल में हुई ऐतिहासिक भारत यात्रा के बाद से हुई प्रगति की समीक्षा की और यह सुनिश्चित करने के लिए साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई कि हम अपने संबंधों की गति को बनाए रखेंगे। सीमा के प्रश्न पर हमारा काम जारी रहेगा; हमारे विशेष प्रतिनिधि जल्द ही मिलेंगे। हमारा द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, जैसा कि हम लोगों ने आशा की थी। हम संयुक्त अध्ययन दल की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि हमारे आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को उपयुक्त ढंग से आगे बढ़ाया जा सके।

संक्षेप में, मुझे लगता है कि मेरा यह दौरा काफी लाभदायक और उपयोगी रहा है।

.....